



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड. (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120]

No. 120]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 9, 2004/फाल्गुन 19, 1925

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 9, 2004/PHALGUNA 19, 1925

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2004

सा.का.नि. 178(अ).—सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 29 की उप-धारा (2) के खंड (च) तथा धारा 15ड. के साथ पठित धारा 15ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (पीठासीन अधिकारी के वेतन तथा भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 1997 के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः -

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ : (1) इन नियमों को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (पीठासीन अधिकारी एवं अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2003 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो --

(क) “अधिनियम” से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है ;

(ख) “पीठासीन अधिकारी” से अधिनियम की धारा 15ठ के तहत प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ग) “सदस्य” से अधिनियम की धारा 15ठ के तहत प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(घ) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित न किए गए अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, क्रमशः वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में इन्हें समुद्देशित किए गए हैं।

3. पीठासीन अधिकारी और सदस्यों की सेवा शर्तें : प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से गठित की जाने वाली चयन समिति की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी।

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :-

- (i) गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक या उनके नामिती
- (ii) वित्त सचिव/सचिव, आर्थिक कार्य विभाग
- (iii) पीठासीन अधिकारी, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण

चयन समिति यह संतुष्टि करेगी कि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी या सदस्य के लिए अनुशंसित व्यक्ति अधिनियम में, अथवा नियमावली में यथा निर्धारित शर्तों को पूरा करता है तथा उसका कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिससे पीठासीन अधिकारी या सदस्य के रूप में इसके कार्यों पर पूर्वाग्रहपूर्व प्रभाव पड़ने की संभावना है।

सरकार को समिति द्वारा पुनः विचार्य तथा नया नाम/पेनल प्रस्तुत करने हेतु नाम/पेनल को वापस करने का अधिकार होगा।

पीठासीन अधिकारी या सदस्य की कोई नियुक्ति मात्र किसी रिक्ति या चयन समिति के गठन में कोई दोष होने के कारण अवैध नहीं होगी।

4. वेतन :- प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी को वही वेतन दिया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश को अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को अनुज्ञेय है।

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य को वही वेतन दिया जाएगा जो भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय है।

वशर्त कि यदि पीठासीन अधिकारी या सदस्य पेंशन, उपदान, अंशदायी भविष्य निधि में नियोजक के अंशदान इत्यादि के रूप में कोई सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहा है तो ऐसे पीठासीन अधिकारी/सदस्य के वेतन में से उराके द्वारा आहरित या आहरित की जाने वाली पेंशन की सकल राशि या अंशदायी भविष्य निधि में नियोजक के अंशदान की राशि अथवा किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति लाभ की राशि को कम कर दिया जाएगा।

5. **पेंशन तथा भविष्य निधि :** यदि पीठासीन अधिकारी, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण का पद उच्चतम न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा धारित है तथा सदस्य का पद केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा अन्य किसी पेंशन योग्य सेवा के अधिकारी द्वारा धारित है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति अथवा केन्द्र सरकार के अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में प्रदत्त सेवा की उस सेवा, जिससे वह संबंधित है, के नियमों के अनुरूप उससे द्वारा आहरण की जाने वाली पेंशन के लिए गणना की जाएगी। वह सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियमावली, 1960 के उपबंधों द्वारा भी शासित होगा। अन्य सभी मामलों में, व्यक्ति अंशदायी भविष्य निधि के लिए हकदार होगा।

6. **यात्रा भत्ता :** पीठासीन अधिकारी, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण दौरे पर अथवा स्थानांतरण के दौरान (जिसमें प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिए की गई यात्रा अथवा प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में कार्यकाल की समाप्ति पर अपने गृह नगर जाने के लिए की गई यात्रा शामिल हैं) यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, वैयक्तिक चीजवरत के परिवहन तथा ऐसी ही अन्य बातों के संबंध में, उन्हीं मापमान और उन्हीं दरों से हकदार होगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश/उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के लिए प्रयोज्य हैं। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य दौरे पर या स्थानांतरण के दौरान (जिसके अन्तर्गत प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिए या प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण से उस कार्यकाल की समाप्ति पर स्वनगर जाने के लिए की गई यात्रा भी शामिल हैं) यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, वैयक्तिक चीजवरत के परिवहन और ऐसी ही अन्य बातों के संबंध में उन्हीं मापमान और उन्हीं दरों से हकदार होगा जो समतुल्य वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के समूह “क” के अधिकारियों पर प्रयोज्य हैं।

7. **छुट्टी यात्रा रियायत :** प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी उन्हीं दरों से और उसी मापमान पर छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा जो उच्चतम न्यायालय अथवा उस राज्य जिसमें न्यायाधिकरण अवस्थित है, के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर प्रयोज्य है। सदस्य प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण उन्हीं दरों से तथा उसी मापमान पर छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा जो समतुल्य वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार /राज्य सरकार के समूह “क” के अधिकारियों पर प्रयोज्य हैं।

8. **सवारी की सुविधा :** प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी या सदस्य स्टाफ कार और प्रत्येक मास डेढ़ सौ लीटर पेट्रोल या प्रत्येक मास वास्तव में उपभोग किए पेट्रोल का, इनमें से जो भी कम हो, हकदार होगा।

9. **चिकित्सीय उपचार की सुविधाएं :** प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी अथवा सदस्य अंशदायी स्वास्थ्य सेवा स्कीम नियमावली, 1954 में यथा उपबंधित चिकित्सीय उपचार तथा अस्पताल सुविधाओं का हकदार होगा और उन स्थानों में जहां केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा स्कीम प्रवर्तन में नहीं है, वहां उक्त पीठासीन अधिकारी केन्द्रीय सेवा चिकित्सीय परिचर्या नियम, 1944 में यथा उपबंधित सुविधाओं का हकदार होगा।

10. **लाभकर हित का प्रकटन :** प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी तथा सदस्य उनके समक्ष निर्णय हेतु आने वाले प्रतिभूतियों या बाजार मध्यवर्तियों या निकायों से जुड़े मामलों में अपने निकट संबंधियों सहित अपने हित का प्रकटन करेंगे तथा उन मामलों के निर्णयन में भाग नहीं लेंगे।

11. **हित के संभाव्य संघर्ष वाले संबंधों का विच्छेद :** प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी अथवा सदस्य पद को धारण करने वाला व्यक्ति प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी/सदस्य के पद से इस्तीफा देने की तारीख से कम से कम दो वर्ष के लिए प्रतिभूति बाजार से संबंधित किसी कंपनी, बाजार मध्यस्थ, संस्था, एजेंसी अथवा अन्य व्यक्ति के साथ नियोजन के लिए अर्हक नहीं होगा जब तक कि उसने इस प्रयोजन हेतु केन्द्र सरकार से विशिष्ट पूर्व अनुमोदन नहीं प्राप्त कर लिया हो।

12. **निष्कासन एवं त्यागपत्र :** केन्द्र सरकार अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी सदस्य को उसके पद से निष्कासित कर सकती है, जिसे

- (क) दिवालिया घोषित कर दिया गया हो ; अथवा
- (ख) जिसे किसी अपराध, जो केन्द्र सरकार के विचार में नैतिक चरित्रहीनता से संबंधित है, के लिए सिद्धदोष किया गया हो ; अथवा
- (ग) जो पीठासीन अधिकारी अथवा सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक अथवा मानसिक रूप से असक्षम हो गया हो ; अथवा
- (घ) जिसने ऐसा वित्तीय अथवा अन्य हित हासिल कर लिया हो जिससे उसके पीठासीन अधिकारी अथवा सदस्य के रूप में कार्यों पर पूर्वाग्रह पूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना हो।
- (ङ.) जिसने ऐसा दुर्यवहार किया है अथवा अपने पद का दुरुपयोग किया है जिक्रे कारण उसका पदधारण किए रखना जनहित के लिए प्रतिकूल हो।

- (2) उप-धारा (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी अथवा सदस्य को उप-धारा (1) के खंड (क) से (ड.) में निर्दिष्ट आधार पर नहीं हटाया जाएगा सिवाए तब जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच करने, जिसमें संबंधित पीठासीन अधिकारी अथवा सदस्य को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के बारे में सूचित किया गया है तथा सूचित इन आरोपों के संबंध में कि पीठासीन अधिकारी अथवा सदस्य को ऐसे आधार पर अथवा आधारों पर निष्कासित किया जाना चाहिए, सफाई देने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है, के पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा आदेश दे दिया गया हो।
- (3) केन्द्र सरकार अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी अथवा सदस्य जिसके संबंध में उप-धारा (2) के तहत उच्चतम न्यायालय को संदर्भ भेजा गया है, को उसके पद से निलंबित कर सकती है जब तक कि केन्द्र सरकार ने इस संदर्भ पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर आदेश जारी न किया हो।

13. अविशिष्टीय शक्तियां : प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी या सदस्यों की सेवा शर्तों से संबंधित मामले, जिनके बाबत इन नियमों में कोई सुस्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार को उसके निर्णय के लिए भेजे जाएंगे और केन्द्रीय सरकार का उन पर निर्णय उक्त पीठासीन अधिकारी या सदस्य पर आबद्धकर होगा।

14. शिथिल करने की शक्ति : केन्द्रीय सरकार को इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में शिथिल करने की शक्ति प्राप्त होगी।

[फा. सं. 5/58/सीएम/2002]

यू. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2004

G.S.R. 178(E).— In exercise of the powers conferred by section 15 L read with section 15 M and clause (f) of sub-section (2) of section 29 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and in supercession of the Securities Appellate Tribunal (Salaries and allowances and other conditions of service of the Presiding Officer) Rules, 1997, the Central Government hereby makes the following rules namely : -

1. Short title and Commencement – (1) These rules may be called the Securities Appellate Tribunal (Salaries, Allowance and other Terms and Conditions of Presiding Officer and Other Members) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions – In these rules, unless the context otherwise required -

- (a) “Act” means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
- (b) “Presiding Officer” means a person appointed as Presiding Officer of the Securities Appellate Tribunal under section 15 L of the Act;
- (c) “Member” means a person appointed as Member of the Securities Appellate Tribunal under section 15 L of the Act;
- (d) all other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Terms and conditions of Service of Presiding Officer and Members – The Presiding Officer of the Securities Appellate Tribunal shall be appointed by the Central Government on the recommendation of Selection Committee to be constituted in consultation with the Chief Justice of India.

The Members of the Securities Appellate Tribunal shall be appointed by the Central Government on the recommendation of a Selection Committee comprising of

- (i) Governor, Reserve Bank of India or his nominee

- (ii) Finance Secretary/Secretary, Department of Economic Affairs.
- (iii) Presiding Officer, Securities Appellate Tribunal

The Selection Committee shall satisfy itself that the person recommended for Presiding Officer or Member, Securities Appellate Tribunal meets the requirement as prescribed in the Act, or the Rules and does not have any financial or other interest which is likely to affect prejudicially his functions as the Presiding Officer or a Member.

The Government shall have the right to return the name/panel for reconsideration by the Committee and for submission of a fresh name/panel.

No appointment of the Presiding Officer or Member shall be invalid merely by reason of any vacancy or any defect in the constitution of the Selection Committee.

4. Salary -- The Presiding Officer of Securities Appellate Tribunal shall be paid such salary as admissible to a serving Judge of Supreme Court or the Chief Justice of a High Court.

A Member of Securities Appellate Tribunal shall be paid such salary as admissible to a Secretary to the Government of India.

Provided that if the Presiding Officer or a Member is in receipt of any retirement benefit by way of pension, gratuity, employer's contribution to Contributory Provident Fund, etc., the pay of such Presiding Officer/Member shall be reduced by the gross amount of pension or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefit, if any, drawn or to be drawn by him.

5. Pension and Provident Fund. -- In case a serving Supreme Court Judge or Chief Justice of a High Court is holding the post of Presiding Officer, Securities Appellate Tribunal and an officer of Central Government or State Government or any other pensionable service is holding the post of Member, the service rendered by Supreme Court Judge or Chief Justice of a High Court or an Officer of the Central Government as the case may be in Securities Appellate Tribunal will count for pension to be drawn by him in accordance with the rules of the service to which he belongs. He shall also be governed by the provisions of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960. In all other cases, a person shall be entitled to Contributory Provident fund.

6. Travelling Allowance -- The Presiding Officer, Securities Appellate Tribunal while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join Securities Appellate Tribunal or on the expiry of his term with the Securities Appellate Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to traveling allowance, daily allowances, transportation of personal effects and other similar matters at the same scale and at the same rates as are applicable to Supreme Court Judge/Chief Justice of High Courts. The Members of Securities Appellate Tribunal, while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join Securities Appellate Tribunal or on the expiry of his term with the Securities Appellate Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to travelling allowance, daily allowances, transportation of

personal effects and other similar matters at the same scale and at the same rates as are application to Group 'A' officers of the Central Government or State Government drawing an equivalent pay.

7. Leave Travel Concession -- The Presiding Officer of Securities Appellate Tribunal shall be entitled to leave Travel Concession at the same rates and at the same scale as are applicable to the Judge of the Supreme Court or a high Court in the State in which the Tribunal is located. Member, Securities Appellate Tribunal shall be entitled to leave travel concession at the same rates and at the same scale as are applicable to Group 'A' officers of the Central Government/State Government drawing equivalent pay.

8. Facility of Conveyance -- The Presiding Officer or Member of Securities Appellate Tribunal shall be entitled to staff car and 150 liters of petrol every month or actual consumption of petrol per month, whichever is less.

9. Facilities of Medical Treatment -- The Presiding Officer or Member of Securities Appellate Tribunal shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Contributory Health Services Rules, 1954 and in places where Central Health Services Scheme is not in operation, the said Presiding Officer shall be entitled to the facilities as provided in the Central Services Medical Attendance Rules, 1944.

10. Disclosure of beneficial interest -- Presiding Officer and Member of Securities Appellate Tribunal shall disclose their interest including of their close relatives in matters relating to securities or market intermediaries or entities, coming up for decision before them, and not to participate in the decision making in those cases.

11. Severance of ties entailing potential conflict of interest -- A person holding the post of Presiding Officer or Member of Securities Appellate Tribunal shall not be eligible to take up any employment with any company, market intermediary, institution, agency or any other person associated with securities market for at least two years from the date on which he demitted the office of Presiding Officer/Member, Securities Appellate Tribunal, unless specific prior approval for the purpose is obtained from the Central Government.

12. Removal and Resignation -- (1) The Central Government may remove from office, the Presiding Officer or any Member of the Appellate Tribunal, who-

- (a) has been adjudged an insolvent; or
- (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government involves moral turpitude; or
- (c) has become physically or mentally incapable of acting as the Presiding Officer or a Member; or
- (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the Presiding Officer or a Member; or
- (e) has so misbehaved or abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Presiding Officer or a Member of the Securities Appellate Tribunal shall not be removed from his office on the ground specified in clauses (a) to (e) of sub-section (1) except by an Order by the Central Government after an inquiry made by a Judge of the Supreme Court, in which the Presiding Officer or any other Member concerned has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity or being heard in respect of these charges reported that the Presiding Officer or a Member ought on such ground or grounds to be removed.
- (3) The Central Government may suspend from office, the Presiding Officer or a Member of the Appellate Tribunal in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under sub-section (2), until the Central Government has passed an order on receipt of the report of the Supreme Court on such reference.

13. Residuary Powers – Matters relating to the conditions of service of the Presiding Officer or Members of Securities Appellate Tribunal with respect to which no express provision is made in these rules shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on the said Presiding Officer or Member.

14. Power to relax – The Central Government shall have the power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or category or persons.

[F. No. 5/58/CM/2002]
U. K. SINHA, Jt. Secy.